विश्वकी नजर म्यांमारपर

❑ शशिधर खान

सिविलियन वर्दीधारी सैनिक शासनवाले म्यांमारके नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियोंको २३ अप्रैलको संसद सदस्यके रूपमें शपथ लेनी है। इस ऐतिहासिक मौकेपर प्रमुख पश्चिमी देशोंके गणमान्य राजनयिक मौजूद रहेंगे। उसके बाद म्यांमारके खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध हटानेपर गम्भीरतासे विचार किया जायगा, क्योंकि ५० वर्षोंकी एकछत्र तानाशाहीमें पहली बार विपक्ष नामकी कोई चीज होगी। २७ देशोंके यूरोपीय संघ विदेशमन्त्रियोंने २३ अप्रैलको ही बैठक बुला रखी है, जबं प्रतिबन्ध हटानेसे सम्बन्धित अगले कदमोंपर विमर्श होनेकी सम्भावना है।

ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री डेविड केमीरोन दस दिन पहले ही स्थितिका जायज लेने म्यांमारकी राजधानी यांगुन पहुंच गये। लोकतन्त्र समर्थकोंपर जुल्म ढाये जानेके कारण म्यांमारके खिलाफ प्रतिबन्ध लगाकर इससे राजयनिक सम्पर्क तोड़नेवाला पहला ब्रिटेन है। १९४७ में ब्रिटेनके उपनिवेशिक शासनसे मुक्त होनेके बाद किसी ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीकी यह पहली म्यांमार यात्रा थी। सैनिक वर्दी उतारकर सिविलियन ड्रेस धारण करके जनरलसे 'सुधारवादी' राष्ट्रपति बने थेइन सेइन द्वारा २०११ से शुरू किये गये लोकतन्त्र बहालीपर पश्चिमकी इतनी पैनी नजर है कि ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री वहांकी अभिशप्त जनताका हाल जानने स्वयं पहुंच गये। केमीरोन तो प्रोटोकालका पालन करते हुए १३ अप्रैलको राष्ट्रपतिसे मुलाकातके बाद लोकतन्त्रकी लहर जगानेवाली विपक्षी नेता ऑंग सान सूकीसे उनके आवासपर जाकर मिले।

सूकीसे बातचीतके दौरान केमीरोनने कहा म्यांमारके खिलाफ कुछ प्रतिबन्धोंको स्थगित रखा जा सकता है, लेकिन हटानेपर विचार करनेके लिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। सूकीने उनका समर्थन किया। केमीरोनके यांगून आनेसे एक दिन पहले सूकीकी पार्टी नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी, एनएलडी, प्रवक्ता न्यान विनने साफ शब्दोंमें कह दिया कि सैनिक सरकारको स्थायी रूपसे कायम रखनेवाले प्रावधानोंसे लेबरेज संविधानके प्रति आस्था व्यक्त करके संसद सदस्यताकी शपथ लेना जन भावनाओंके खिलाफ जायगा।

१९६२ में तख्तापलट करके सैनिक शासनकी नींव रखनेवाले जनरलने, विनने १९६४ में ऐसा संविधान बनाया जिसमें अपनी वर्मा सोसलिस्ट प्रोग्राम पार्टीके लिए कभी विपक्षमें आनेके साथ ऐसी स्थायी व्यवस्था भी की गयी कि विपक्ष नामकी कोई चीज हो ही नहीं । वे समय-समयपर चुनाव कराते थे, लेकिन उसकी कोई संविधान सम्मत निर्धारित अवधि नहीं थी। उसके लिए चुनाव आयोग भी था, लेकिन मतदाताओंके पास विकल्प नहीं होता था। दूसरी पार्टी या संघटन बनानेकी छूट ही नहीं थी। १९८८ के राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनको कुचलनेकी सारी कोशिशोंके बावजूद ने विनको तो इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सैनिक शासन कायम रहा। ने विनके उत्तराधिकारियोंने सत्तारूढ़ पार्टीका नाम कई बार बदला, देश और राजधानीका नाम बदला, मगर संविधानका मूल ढांचा सेनाका वर्चस्ववाला ने विन शासनकालका ही रहा। १९९० के चुनावसे पहले अन्तरराष्ट्रीय दबावमें सूकी समर्थकोंको पार्टी बनानेकी छूट दी गयी। लेकिन चुनावमें सैनिक जुंटा पार्टीने विपक्षमें जानेवाला जनादेश स्वीकार करनेके बजाय भारी मतोंसे जीते प्रतिनिधियोंको संसदके बजाय जेल भेज दिया। उनके नेता सूकीको अपने घरमें ही नजरबन्द कर दिया। फिर २०१० में संविधानमें ऐसे सुधार करके चुनाव कराये गये, ताकि कोई विपक्षी उम्मीदवार पर्चा ही नहीं भर सके। नेशनल लीग फार डेमोक्रेसीकी मान्यता चुनाव आयोगने समाप्त कर दी और ऐसे उम्मीदवारोंके पर्चे रद करनेके प्रावधान किये गये जिनका सरकार विरोधी रिकार्ड रहा हो।

सूकी समेत सारे विरोधी चुनावके दौरान जेलमें रहे। चुनावमें सत्तारूढ़ पार्टीकी 'भारी जीत' के बाद पहले सूकीको और फिर उनके समर्थकोंको सुधार कार्यक्रमोंके तहत रिहा किया गया। संसदमें विपक्षकी भूमिकाके लिए स्थान नहीं है। लेकिन विपक्षको न उभरने देनेके सारे उपाय किये हैं। सिर्फ सेना संचालित पार्टीको कानूनी मान्यता देनेवाले ऐसे संविधानके प्रति आस्था व्यक्त करके विपक्षी सदस्य क्या भूमिका निभायंगे, यह सोचनेवाली बात है, जिसमें जनहितके मुद्दे उठाना 'असंवैधानिक' माना जा सकता है। विपक्षवाले पहलूकी कई बातें दिग्भ्रमित करनेवाली हैं, जिसपर सैनिक सरकारने चुप्पी साध रखी है। इससे सम्बन्धित सुधारकी दिशामें अभीतक क्या कदम उठाये गये हैं, यह भी गोलमटोल है। ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीकी ऐतिहासिक यात्रासे दो दिन पहले राष्ट्रपति थेइन सेइनकी ऑंग सान सूकीसे 'बन्द कमरेमें बातचीत' हुई, जिसका ब्योरा देनेसे सूकीने भी इनकार कर दिया।

सूकीने संवाददाताओंसे सिर्फ इतना ही कहा कि मैं राष्ट्रपतिके यहां 'पारिवारिक भोज' पर आमन्त्रित हूं। नवम्बर, २०११ के अन्तमें अमेरिकाकी विदेशमन्त्री हिलेरी क्लिंटनके ऐतिहासिक म्यांमार दौरेके बाद यांगून पहुंचनेवाले दूसरे महत्वपूर्ण राजनयिक ब्रिटेनके विदेशमन्त्री विलियम हेग थे। लेकिन इस सैनिक तानाशाहीवाले देशमें भारत समेत अन्य जनतान्त्रिक देशोंकी तरह संसदमें विपक्षी नेता जैसा कैबिनेट मन्त्रीका दर्जा प्राप्त कोई पद नहीं है। वहां सूकी और उनके समर्थक सांसद सरकारके 'लोकतन्त्र बहाली' उपायोंमें किस प्रकार और क्यास सहयोग करेंगे, यह भी अस्पष्ट है। सूकीने राष्ट्रपतिसे मुलाकातके बाद सरकारमें कोई पद हासिल करनेकी सम्भावना सरकारी प्रचारके मुताबिक तो इनकार कर दिया, लेकिन प्रतिबन्धित करने विद्रोहियोंके समर्थनमें सलाहकारकी भूमिका निभानेपर सहमति व्यक्त की।